भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1415

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-केएमवाई को बढ़ावा देने के अभियान

1415. श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री संजय दिना पाटीलः

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः

श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर महाराष्ट्र में छोटे और सीमांत किसानों के बीच प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई) जैसी पेंशन योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के कतिपय जिलों में पीएम-केएमवाई के अंतर्गत कम नामांकन के कारणों की पहचान की है और यदि हां, तो उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र के जनजातीय, सूखा-प्रवण और दूरस्थ क्षेत्रों में उन किसानों, जिनकी नामांकन के लिए आवश्यक बैंकिंग या डिजिटल सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, तक पहुंच बनाने के लिए कोई लक्षित प्रयास किए गए हैं;

(घ) महाराष्ट्र में इस योजना के अंतर्गत जागरूकता उत्पन्न करने और नामांकन में सहायता करने में सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी), कृषि सखियों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की क्या भूमिका है; और

(ङ) महाराष्ट्र में वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने और किसान पेंशन योजनाओं के संबंध में सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सरकार की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ): "प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)" एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन 3000/- रुपये की न्यूनतम मासिक

सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान है, जो बहिष्करण मानदंडों के अधीन है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों के लिए उनकी वृद्धावस्था के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा नेट बनाना है। योजना में किसानों की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान की राशि 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच है। भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) इस योजना के लिए निधि प्रबंधक है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत किसानों का नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है और पीएम-केएमवाई योजना के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सीएससी द्वारा एक समर्पित पोर्टल बनाया गया है। सरकार, इस योजना के अंतर्गत किसानों के नामांकन के लिए समय-समय पर अभियान चलाती है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सहित छोटे और सीमांत किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत नामांकन दर के प्रभावित होने का कारण है कि पीएम-केएमवाई योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है और केवल 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है, जिनकी संख्या कम है। इसके अलावा, एक ऐसी ही योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) भी है, जो कि पीएम-केएमवाई के आरंभ से पहले से ही लागू है।

*****